भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2874
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र

2874. श्री अतुल गर्गः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गाजियाबाद के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच, डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं और डिजिटल वित्तीय समावेशन और ई-लर्निंग सेवाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;
(ग) सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय और तीव्र गति की इंटरनेट पहुँच को किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है और गाजियाबाद में भारत नेट परियोजना की स्थिति क्या है;
(घ) सरकार द्वारा कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए ग्रामीण डिजिटल उद्यमिता, ऑनलाइन नौकरी प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स पहुंच को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) गाजियाबाद के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 5जी संपर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए सरकार की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है । इंटरनेट की पहुँच, डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए की गई कई पहलें इस प्रकार हैं:

1. **कनेक्टिविटी** : देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।

   दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर रहा है। देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार किया जा चुका है।

   गाजियाबाद जिले में 151 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर दिया गया है।

2. " **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** " के अंतर्गत देश भर में 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। गाजियाबाद जिले में 183 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए गए, जिनमें 26,003 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** : ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए सीएससी की स्थापना की गई है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जिसका संचालन ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा किया जाता है।

   सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार, शिक्षा, टेली मेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

देश भर में 5.60 लाख से ज़्यादा सीएससी (ग्रामीण+शहरी) कार्यरत हैं, जिनमें से 4.36 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं। गाजियाबाद ज़िले में 1,450 सीएससी (ग्रामीण+शहरी) कार्यरत हैं, जिनमें से 402 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर हैं।

4. **स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम)** शुरू किया गया है। यह विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, रि-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

   इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) शामिल हैं, जो देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए हैं।

   एसआईएम का उद्देश्य भारत के कुशल श्रमिकों को उद्योग प्रासंगिक कौशल के साथ भविष्य के लिए तैयार करना है।

5. **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** 49 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता और 675 बैंक यूपीआई से जुड़कर इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बना चुके हैं। इससे नागरिकों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को भी मदद मिली है।

6. **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)** एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) की मौजूदा मंडियों को जोड़कर कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाता है। ई-नाम पर 1.79 करोड़ से ज़्यादा किसान और 4,518 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत हैं।

7. **Indiahandmade.com** एक डिजिटल बाज़ार है जो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

   इस ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बुनकरों और कारीगरों को भारत में अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे बिचौलियों को खत्म करते हुए कारीगरों और बुनकरों के कौशल को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।

8. **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी)** : ओएनडीसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक प्रौद्योगिकी पहल है जिसका उद्देश्य एक विकेन्द्रीकृत ओपेन ई-कॉमर्स मॉडल को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है, जिससे डिजिटल कॉमर्स में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

   ओएनडीसी डिजिटल एकाधिकार को कम करता है, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए पहुंच बढ़ाता है, तथा भारत में ई-कॉमर्स की पहुंच बढ़ाता है।

9. **5जी सेवाएँ** शुरू कर दी गई हैं और यह देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा देश भर में 4.86 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं।

10. **इंडिया एआई मिशन** : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार सभी के लिए तकनीक सुलभ बना रही है। इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन में सुधार हो सके।

    इंडियाएआई मिशन में लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेही, सुरक्षा, निष्पक्षता और मानवाधिकारों एवं गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

*****